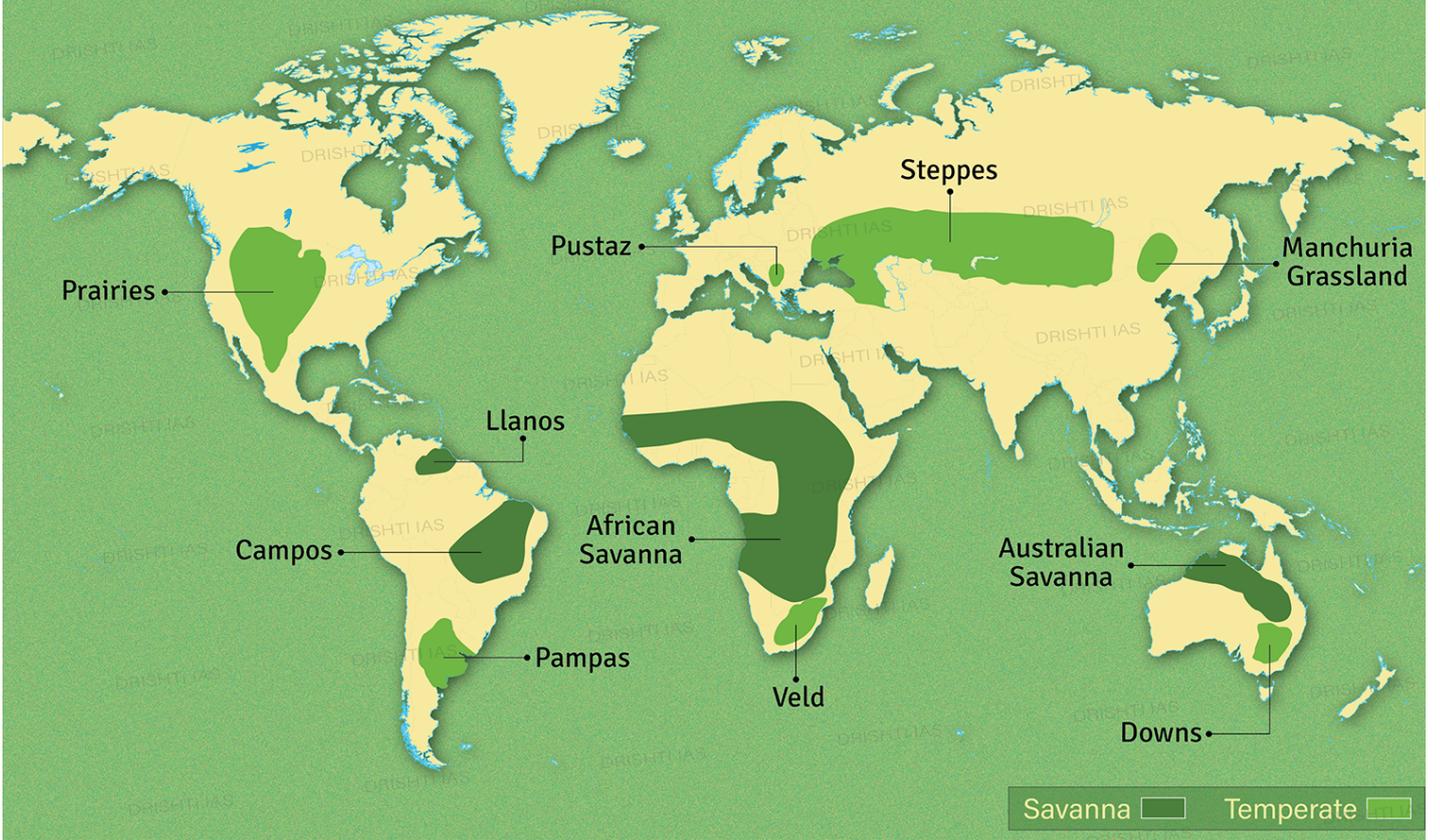


वर्श्व के घास के मैदान

//

वर्श्व के घास के मैदान



तथ्य

- घास के मैदान मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं: उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण। समशीतोष्ण घास के मैदानों के उदाहरणों में यूरेशिया के स्टेपी, उत्तरी अमेरिका के प्रेयरी और अर्जेंटीना के पम्पास शामिल हैं। उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में उप-सहारा अफ्रीका और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के गर्म सवाना शामिल हैं।
- उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में मौसम शुष्क एवं आर्द्र होता है जो हर समय गर्म रहते हैं (तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस)। समशीतोष्ण घास के मैदानों में शीत ऋतु ठंडी और ग्रीष्म ऋतु कुछ बारिश के साथ गर्म होती है (सर्दियों में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे और गर्मियों में 32 डिग्री तक)।
- घास के मैदानों के अस्तित्व के लिये चनाग्नि महत्वपूर्ण है; वे काष्ठीय पौधों (woody plants) के प्रसार को रोकते हैं और घास को पुनः स्थूलता के साथ व स्वस्थ रूप में वृद्धि करने में सक्षम बनाते हैं।

प्रलम्ब के लिये:

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु-वजिज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (NMHP), मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017, करिण हेल्पलाइन, मानसिक स्वास्थ्य और सामान्यता वृद्धि प्रणाली (MANAS), गरीबी, आयुष्मान भारत ।

मेन्स के लिये:

भारत में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल की स्थिति, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे, भारत सरकार की मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित पहल ।

चर्चा में क्यों?

वशिव स्वास्थ्य संगठन (World Health Organisation- WHO) के अनुसार, वर्ष 2019 में भारत में आत्महत्या दर 12.9/1,00,000 थी, जो क्षेत्रीय औसत 10.2 और वैश्विक औसत 9.0 से अधिक थी ।

- भारत में 15 से 29 वर्ष के बीच के लोगों की मृत्यु दर का मुख्य कारण आत्महत्या है । हालाँकि आत्महत्या के कारण खोया गया प्रत्येक जीवन बहुत अधिक कीमती है, लेकिन यह मुश्किल से ही देश के मानसिक स्वास्थ्य विशेष रूप से युवा वयस्कों को प्रभावित करने वाले मुद्दों को उजागर करता है । महिलाएँ इस समस्या से आमतौर पर अधिक प्रभावित होती हैं ।

भारत में मानसिक स्वास्थ्य सेवा की स्थिति:

परिचय:

- मानसिक स्वास्थ्य में भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कल्याण शामिल है ।

- यह अनुभूति, धारणा और व्यवहार को प्रभावित करता है । साथ ही यह भी निर्धारित करता है कि कोई व्यक्ति तनाव, पारस्परिक संबंधों और नरिणय लेने की स्थिति का सामना कैसे करता है ।

- भारत में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु-वजिज्ञान संस्थान (National Institute of Mental Health and Neuro-Sciences) के आँकड़ों के अनुसार, कई कारणों से 80% से अधिक लोगों की मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच नहीं है ।

मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित भारत सरकार की पहल:

- राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (National Mental Health Program- NMHP): मानसिक विकारों की संख्या में वृद्धि तथा मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की कमी को देखते हुए सरकार द्वारा वर्ष 1982 में NMHP को अपनाया गया था ।
- मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम: मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 के एक भाग के रूप में प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति के लिये सरकारी संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और उपचार की सुविधा एवं पहुँच उपलब्ध है ।
- करिण हेल्पलाइन: वर्ष 2020 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रदान करने के लिये 24/7 टोल-फ्री हेल्पलाइन 'करिण' शुरू की ।
- मानस मोबाइल एप: भारत सरकार ने सभी आयु समूहों में मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिये वर्ष 2021 में मानस (मानसिक स्वास्थ्य और सामान्यता वृद्धि प्रणाली) लॉन्च किया ।

मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे:

- सोशल मीडिया: गनि-चुने सोशल मीडिया के बढ़ते उपयोग के साथ युवाओं में तनाव और मानसिक अस्वस्थता के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है ।

- सोशल मीडिया वास्तविक दुनिया से परे है और यह सार्थक गतिविधियों में नविश को कम करता है ।

- इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह प्रतिकूल सामाजिक तुलना के माध्यम से आत्मसम्मान में कमी लाता है ।

- कोविड-19 महामारी: कोविड-19 महामारी के बाद से इस समस्या में और वृद्धि हुई है । लैसेट में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, वर्ष 2020 और 2021 के बीच केवल एक वर्ष में वैश्विक स्तर पर इस महामारी के कारण अवसाद में 28% तथा चिंता संबंधी मामलों में 26% तक की वृद्धि हुई है ।

- स्कूल बंद होने और सामाजिक अलगाव के अतिरिक्त भविष्य संबंधी अनिश्चितता, वित्तीय एवं रोज़गार का नुकसान, दुख, बच्चों की देखभाल का बढ़ता बोझ आदि सभी के कारण भी युवा आयु समूहों के बीच अवसाद तथा चिंता में वृद्धि देखी गई है ।

- नरिधनता: मानसिक स्वास्थ्य का नरिधनता से करीबी रिश्ता होता है । गरीबी में रहने वाले लोगों को मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की स्थिति का अनुभव होने का खतरा अधिक होता है ।

- दूसरी ओर गंभीर मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों का सामना करने वाले लोगों को रोज़गार के नुकसान और स्वास्थ्य पर व्यय में वृद्धि के कारण गरीबी की ओर बढ़ने की अधिक संभावना है ।

- मानसिक स्वास्थ्य बुनियादी ढाँचे की कमी: वर्तमान में मानसिक बीमारियों वाले केवल 20-30% लोगों को पर्याप्त उपचार मिला

पाता है।

- इतने बड़े उपचार अंतराल का एक प्रमुख कारण संसाधनों की अपर्याप्तता है। सरकार के स्वास्थ्य बजट का 2% से भी कम मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के लिये उपलब्ध है।

- साथ ही [आवश्यक दवाओं की सूची](#) में WHO द्वारा निर्धारित मानसिक स्वास्थ्य दवाओं की सीमिति संख्या ही शामिल है।

भारत में मानसिक स्वास्थ्य संवर्द्धन की पुनर्कल्पना:

हमारे लोगों के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा, संवर्द्धन और देखभाल के लिये एक तत्काल और अच्छी तरह से संसाधन युक्त "संपूर्ण समाज" के दृष्टिकोण की आवश्यकता है। यह नमिनलखिति चार स्तंभों पर आधारित होना चाहिये:

- मानसिक स्वास्थ्य को कलंक न समझना: मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को कलंक मानना, जो रोगियों को समय पर इलाज कराने से रोकता है और उन्हें शर्मनाक, अलग-थलग एवं कमजोर महसूस कराता है।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में मानसिक स्वास्थ्य को शामिल करना: तनाव को कम करने, स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने, उच्च जोखिम वाले समूहों की जाँच और पहचान करने एवं परामर्श सेवाओं जैसे मानसिक स्वास्थ्य हस्तक्षेपों को मज़बूत करने के लिये उन्हें मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग बनाना।
 - स्कूलों पर विशेष ध्यान देना होगा।
 - इसके अलावा हमें उन समूहों पर विशेष ध्यान देना चाहिये जो मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं जैसे कि घरेलू या यौन हिंसा के शिकार, बेरोज़गार युवा, सीमांत किसान, सशस्त्र बलों के कर्मी तथा कठिन परिस्थितियों में कार्य करने वाले कर्मी।
- मेंटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर: मेंटल हेल्थ केयर और इलाज के लिये एक मज़बूत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना। मानसिक स्वास्थ्य के बुनियादी ढाँचे और मानव संसाधनों में अंतराल को दूर करने के लिये पर्याप्त निवेश की आवश्यकता होगी।
- कफियाती पहलुओं पर काम करना: मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को सभी के लिये कफियाती बनाया जाना चाहिये। वित्तीय सुरक्षा के बिना बेहतर कवरेज से असमान परिणाम उभरकर सामने आएंगे।
 - [आयुष्यमान भारत](#) सहित सभी सरकारी स्वास्थ्य गारंटी योजनाओं में मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों की व्यापक संभव सीमा को शामिल किया जाना चाहिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न:

प्रश्न. जब तक हम अपने भीतर शांतिप्राप्त नहीं करते, तब तक हम बाहरी दुनिया में कभी भी शांतिप्राप्त नहीं कर सकते। (2021)

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

चनि-कूकी-मज़ि़ो समूह द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियाँ

प्रलिमिस के लिये:

भारत में शरणार्थी, वर्ष 1951 का शरणार्थी सम्मेलन, वर्ष 1946 का विदेशी अधिनियम, नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 (CAA), रोहगिया शरणार्थी, शरणार्थियों के लिये संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त।

मेन्स के लिये:

चनि-कूकी-मज़ि़ो समूह द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियाँ, शरणार्थी संकट, भारत की शरणार्थी नीति।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में चनि-कूकी-मज़ि़ो समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले जो रीयूनफिकेशन ऑर्गनाइज़ेशन (ZORO) ने बांग्लादेश के चटगाँव हलि ट्रैक्ट्स (CHT) में रहने वाले जातीय अल्पसंख्यकों के "उन्मूलन की नीति" को समाप्त करने में भारत से मदद की मांग की है।

- बांग्लादेश की सेना द्वारा रोहगिया मुसलमि चरमपंथी समूह, अराकान आरमी की मलि़ीभगत से एक कथित हमले की घटना के बाद नवंबर 2022

से मज़ोरम के लॉन्गतालाई ज़िले में शरण लेने वाले चनि-कुकी-मज़ो समूह से जुड़े लोगों की संख्या 300 से अधिक है।



बांग्लादेश में चनि-कुकी-मज़ो समूह द्वारा सामना किये जाने वाले मुद्दे:

- बांग्लादेशी सेना द्वारा इन्हें खत्म करने की नीति के कारण चटगाँव हिलि ट्रेक्ट्स (CHT) में स्वदेशी कुकी-चनि जनजातियों के संवैधानिक और मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन किया जा रहा है।
 - CHT दक्षिण-पूर्वी बांग्लादेश में 13,000 वर्ग कमी. का पहाड़ी और जंगली क्षेत्र है, जो भारत के मज़ोरम एवं त्रिपुरा तथा म्यांमार के चनि व रोहिंगियाओं से बसे हुए रखाइन राज्य की सीमा से लगा हुआ है।
- ब्रिटिश पूर्व चटगाँव हिलि ट्रेक्ट्स में स्वशासी सरदार और सरदारनियाँ थीं (Self-governing Chieftdoms and Chieftaincies)। इन समूहों की आबादी को या तो ख्याँगथा के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जो जनजातियाँ नदी के किनारे रहती हैं, या तोंगथा, जो पहाड़ियों के घने जंगलों में रहती हैं।
- ये जनजातियाँ हदू राजाओं और मुस्लिम नवाबों के नियंत्रण से बाहर रहीं, लेकिन वर्ष 1860 में अंग्रेज़ों द्वारा CHT पर कब्ज़े से उन्हें बाहरी दबावों के प्रति संवेदनशील बना दिया।
- अंग्रेज़ों ने जनजातियों की पहचान, रीति-रिवाजों, संस्कृति, परंपरा एवं पैतृक भूमि की रक्षा के लिये CHT को विशेष संवैधानिक दर्जा दिया। हालाँकि प्रतर्बिधात्मक कानूनों को वर्ष 1903 तक नरिस्त कर दिया गया था ताकि भैदानी क्षेत्र के निवासियों को उच्च क्षेत्रों में प्रवेश मिला सके।
- स्थानीय लोगों की अपेक्षाओं के विपरीत CHT को वर्ष 1947 में पाकिस्तान में सम्मिलित कर दिया गया था जिससे सभी स्थानीय जनजातियों को जीवन के सभी पहलुओं में भेदभाव का सामना करना पड़ा।
- जबकि CHT की जनजातीय आबादी में भारी गरिबत आई है, बांग्लादेश सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के नाम पर स्थानीय जनजातियों विशेष रूप से कुकी-चनि लोगों की पैतृक भूमि पर अतिक्रमण कर लिया।

उनकी मांगें:

- CHT की कुकी-चनि जनजातियाँ पहाड़ियों में बड़े पैमाने पर गैर-आदिवासी लोगों की आमद के कारण एक अलग राज्य की मांग कर रही हैं लेकिन बांग्लादेश सरकार ने अपने दमनकारी उपायों को जारी रखने का फैसला किया है।

- ज़ोरो (ZORO) ने भारत से कहा है कि वह अपने बांग्लादेशी समकक्ष को **कुकी-चनि राष्ट्रीय सेना (KNA)** के साथ संघर्ष वरिष्ठ की घोषणा करने तथा CHT में कुकी-चनि लोगों के अधिकारों का दुरुपयोग बंद करने की सलाह दे।
- संगठन ने भारत से गृह मंत्रालय एवं सीमा सुरक्षा बल को यह नरिदेश देने की भी अपील की कि बांग्लादेश से भागकर मज़ोरम में अपनी "स्वजातियों" के बीच शरण लेने वाले कुकी-चनि लोगों को न भगाया जाए।

भारत की शरणार्थी नीति:

- शरणार्थियों की बढ़ती आमद के बावजूद भारत में शरणार्थियों की समस्या के समाधान के लिये वशिष्ट कानून का अभाव है।
- भारत वर्ष **1951 के शरणार्थी सम्मेलन और वर्ष 1967 के प्रोटोकॉल** का पक्षधर नहीं है, जो शरणार्थी संरक्षण से संबंधित प्रमुख कानूनी दस्तावेज़ हैं।
 - हालाँकि शरणार्थी संरक्षण के मुद्दे पर भारत का शानदार रिकॉर्ड रहा है। भारत में वदिशी लोगों और संस्कृतिको आत्मसात करने की एक नैतिक परंपरा है।
- इसके अलावा भारत का संविधान मनुष्यों के जीवन, स्वतंत्रता और गरमा का भी सम्मान करता है।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने **1996** मामले में कहा कि "वदिशी नागरिकों सहित सभी नागरिक समानता के अधिकार और जीवन के अधिकार के हकदार हैं।"
- इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 21 में गैर-प्रत्यावर्तन के अधिकार को शामिल किया गया है।
 - गैर-प्रत्यावर्तन अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत एक सदिधांत है जो कहता है कि अपने देश में उत्पीड़न से भागने वाले व्यक्तिको स्वयं के देश लौटने के लिये मजबूर नहीं किया जाना चाहिये।

भारत में शरणार्थियों की स्थिति:

- अपनी स्वतंत्रता के बाद से भारत ने पड़ोसी देशों के शरणार्थियों के वभिन्न समूहों को स्वीकार किया है, जिनमें शामिल हैं:
 - 1947 में पाकसितान से शरणार्थियों का पलायन।
 - तबिबती शरणार्थी जो 1959 में पहुँचे।
 - 1960 के दशक की शुरुआत में **चकमा और हाजोंग** वर्तमान बांग्लादेश से।
 - 1965 और 1971 में अन्य बांग्लादेशी शरणार्थी।
 - 1980 के दशक के **शरीलंकाई तमलि शरणार्थी**।
 - म्याँमार से **रोहगिया शरणार्थी**।

शरणार्थियों को नयितरति करने हेतु वर्तमान वधायी ढाँचा:

- **1946 का वदिशी अधिनियम:** धारा 3 के तहत केंद्र सरकार को अवैध वदिशी नागरिकों का पता लगाने, हरिसत में लेने और नरिवासति करने का अधिकार है।
- **पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920:** धारा 5 के तहत अधिकारी भारत के संविधान के अनुच्छेद 258(1) के तहत किसी अवैध वदिशी को बलपूर्वक हटा सकते हैं।
- **वदिशी नागरिकि पंजीकरण अधिनियम, 1939:** इसके तहत एक अनविर्य आवश्यकता यह है कि दीर्घकालिक वीज़ा (180 दिनों से अधिक) पर भारत आने वाले सभी वदिशी नागरिकों (भारत के वदिशी नागरिकों को छोड़कर) को भारत आने के 14 दिनों के भीतर पंजीकरण अधिकारी के साथ खुद को पंजीकृत करना आवश्यक है।
 - वदिशियों का पंजीकरण अधिनियम, 1939 और वदिशियों के पंजीकरण के नयिम, 1992 वदिशी पंजीकरण को अनविर्य और वनियमति करते हैं।
- **नागरिकता अधिनियम, 1955:** इसमें अस्वीकार करने, समाप्त और नागरिकता से वंचित करने का प्रावधान है।
- इसके अलावा **नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 (CAA)** केवल बांग्लादेश, पाकसितान और अफगानसितान में सताए गए हट्टि, ईसाई, जैन, पारसी, सखि तथा बौद्ध प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करना चाहता है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्षों के प्रश्न

प्रश्न. नमिनलखिति युग्मों पर वचिर कीजयि: (2016)

समाचारों में कभी-कभी उल्लखिति समुदाय	देश
1. कुरद	बांग्लादेश

2. मधेसी	नेपाल
3. रोहगिया	म्याँमार

उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलति है/हैं:

- (a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2
(c) केवल 2 और 3
(d) केवल 3

उत्तर: (c)

प्रश्न. भारत की सुरक्षा को गैर-कानूनी सीमा पार प्रवसन किस प्रकार खतरा प्रस्तुत करता है? इसे बढ़ावा देने के कारणों को उजागर करते हुए ऐसे प्रवसन को रोकने की रणनीतियों का वर्णन कीजिये। (मुख्य परीक्षा, 2014)

[स्रोत: द हिंदू](#)

वर्ल्ड इकोनॉमिक सचिवालय एंड प्रॉस्पेक्ट्स 2023

प्रलिस के लिये:

GDP, SDG, यूक्रेन में युद्ध, कोविड, महंगाई।

मेन्स के लिये:

वर्ल्ड इकोनॉमिक सचिवालय एंड प्रॉस्पेक्ट्स।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [संयुक्त राष्ट्र](#) ने एक नई रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक सचिवालय एंड प्रॉस्पेक्ट्स 2023 जारी की है, जिसमें कहा गया है कि वैश्विक [सकल घरेलू उत्पाद \(GDP\)](#) के वर्ष 2022 में 3% से गरिकर वर्ष 2023 में 1.9% होने की संभावना है।

- कोविड-19 महामारी, [यूक्रेन में युद्ध](#) और इसके परिणामस्वरूप खाद्य एवं ऊर्जा संकट, बढ़ती मुद्रास्फीति, ऋण सख्ती, साथ ही जलवायु आपातकाल जैसे गंभीर तथा पारस्परिक रूप से सशक्त संघर्ष।

रिपोर्ट के नषिकरष:

- मुद्रास्फीति:** 2022 में दुनिया की औसत [मुद्रास्फीति](#) दर 9% थी, जिसके कारण कई वकिसति और वकिसशील देशों में बजट से संबंधित बाधाएँ उत्पन्न हुईं।
- मंदी:** मौजूदा मंदी ने कोविड-19 संकट से नषितने हेतु आर्थिक सुधार की गतिको धीमा कर दिया है, जिससे वर्ष 2023 **मंदी की संभावनाओं के साथ कई देशों को खतरा** है।
 - अधिकांश वकिसशील देशों ने वर्ष 2022 में रोजगार में धीमी प्रगत देखी है।
 - महामारी के प्रारंभिक चरण के दौरान महिलाओं के रोजगार में अनुपातहीन नुकसान की स्थिति अभी तक पूरी तरह से सामान्य नहीं हुई है।
- वैश्विक उत्पादन में मामूली वृद्धि:** युद्ध की स्थिति में बदलाव और [आपूर्ति शृंखलाओं में व्यवधान के कारण](#) वैश्विक उत्पादन वृद्धि वर्ष 2024 में 2.7% तक हो सकती है।
 - चीन की आर्थिक वृद्धि में वर्ष 2023 में 4.8% और 2024 में 4.5% बढ़ोत्तरी का अनुमान है।
 - अमेरिका द्वारा इस वर्ष 0.4% और वर्ष 2024 में 1.7% की आर्थिक वृद्धि दर्ज किये जाने का अनुमान है।

- **रूसी नरियात:** वर्ष 2022 में रूस के नरियात में वृद्धि हुई क्योंकि चीन, भारत और तुर्किये के साथ व्यापार में वृद्धि हुई।
- **दक्षिण एशियाई परदृश्य:** दक्षिण एशिया में उच्च खाद्य और ऊर्जा की कीमतों, मौद्रिक संकट तथा राजकोषीय कमी के कारण आर्थिक परदृश्य अस्थिर है।
 - औसत सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि जो वर्ष 2022 में 5.6% रही वर्ष 2023 में 4.8% रहने का अनुमान है।
 - वर्ष 2022 में **अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund- IMF)** से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले देशों अर्थात् बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसी अर्थव्यवस्थाओं के लिये संभावनाएँ चुनौतीपूर्ण हैं।

भारतीय परदृश्य:

- **विकास दर:** भारत में विकास दर 5.8% रहने की उम्मीद है, हालाँकि यह वर्ष 2022 में अनुमानित 6.4% से थोड़ा कम है, क्योंकि उच्च ब्याज दर और वैश्विक मंदी नरियात तथा वित्त पर दबाव डालती है।
 - भारत में खाद्य और ऊर्जा संबंधी सब्सिडी ने आर्थिक संकट को दूर रखा।
 - वर्ष 2024 में भारत 6.7% की दर से विकास करेगा, जो वशिव की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
- **मुद्रास्फीति:** वर्ष 2022 के लिये वार्षिक मुद्रास्फीति दर 7.1% रही। वर्ष 2023 में भारत की मुद्रास्फीति दर घटकर 5.5% होने की उम्मीद है क्योंकि वैश्विक उत्पादों की कीमतें मध्यम रहने और मुद्रा मूल्यह्रास की गति धीमी रहने से आयातित मुद्रास्फीति कम हो जाती है।
- **बेरोज़गारी:** वर्ष 2022 में बेरोज़गारी दर शहरी और ग्रामीण रोज़गार में वृद्धि के कारण महामारी पूर्व स्तर तक गरि गई, जो काँक मज़बूत घरेलू मांग का संकेत है।
 - हालाँकि युवा रोज़गार महामारी पूर्व के स्तर से नीचे रहा, वशिषकर युवा महिलाओं के मामले में।

सुझाव:

- **मैक्रोइकोनॉमिक नीतियों का अंशांकन (Calibration):** उत्पादन और मुद्रास्फीति को नयितरि करने के बीच संतुलन बनाने के लिये मैक्रोइकोनॉमिक नीतियों पूर्ण रूप से सही होनी चाहिये।
 - इसके लिये प्रमुख केंद्रीय बैंकों के बीच अधिक प्रभावी समन्वय की आवश्यकता होगी, जो मुद्रास्फीति संबंधी अपेक्षाओं को प्रबंधित और नयितरि करने के लिये सुस्पष्ट नीतियों द्वारा समर्थित हो।
- **इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेडेशन की डी-एकरगि:** मौजूदा ढाँचे में सुधार काफी लाभदायक हो सकता है, केंद्रीय बैंकों को भी वशि्वसनीयता के नुकसान से बचने और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेडेशन की डी-एकरगि के लिये एक सुवचारित एवं व्यापक प्रक्रिया अपनाने की आवश्यकता होगी।
- **सार्वजनिक व्यय को पुनः प्राथमकता देना:** सरकारों को प्रत्यक्ष नीतित हस्तकषेपों के माध्यम से कमज़ोर समूहों की सहायता के लिये सार्वजनिक व्यय को पुनः आवंटित करने और प्राथमकता देने की आवश्यकता होगी।
 - इसके लिये सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों को मज़बूत करने और लक्षित एवं अस्थायी सब्सिडी, नकद हस्तांतरण तथा उपयोगिता बलों पर छूट के माध्यम से नरितर समर्थन सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी।
- **SDG वतितपोषण को बढ़ाना:** आपातकालीन वतिततीय सहायता तक पहुँच बढ़ाने और SDG वतितपोषण को बढ़ाने के लिये मज़बूत अंतरराष्ट्रीय प्रतबिद्धता की तत्काल आवश्यकता है:
 - लक्षित और अस्थायी सब्सिडी, नकद हस्तांतरण और उपयोगिता बलि छूट के माध्यम से नरितर सहायता प्रदान करके सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों को मज़बूत करना, जसि उपभोक्ता करों या सीमा शुल्क में कटौती कर पूरा कया जा सकता है।

स्रोत: डाउन टू अर्थ

भारत के वदियुत बाज़ार का केंद्रीकरण

प्रलिमिस के लिये:

यूरोपीय संघ, बाज़ार आधारित आर्थिक प्रेषण (MBED), वन नेशन वन ग्रडि वन फ्रीक्वेंसी वन प्राइस, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, 2003, वदियुत वतिएण कंपनियों (DISCOMs), नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वहीकल्स।

मेन्स के लिये:

बाज़ार आधारित आर्थिक प्रेषण (MBED) मॉडल, MBED के केंद्रीकृत मॉडल से संबंध चित्ताएँ।

चर्चा में क्यों?

भारत अपनी वदियुत बाज़ार प्रणाली को वकेंद्रीकृत, स्वैच्छिक और अल्पकालिक बाज़ार से एक अनविर्य पूल मॉडल में बदल रहा है जो नशिचित मूल्य

अनुबंधों को समाप्त करता है, जबकि [यूरोपीय संघ](#) इसके विपरीत नीतियाँ अपना रहा है।

वदियुत बाज़ार से संबंधित यूरोपीय संघ की नीति:

- यूरोपीय संघ अपने वदियुत बाज़ार में परविरतन कर रहा है क्योंकि गैस की कमी के कारण वर्ष 2022 में वदियुत की कीमतें काफी बढ़ गई हैं।
 - कीमतें उच्च इसलिये हुईं क्योंकि वदियुत की कीमतें सबसे महँगे वदियुत संयंत्र आमतौर पर गैस संयंत्र द्वारा निर्धारित की जाती हैं।
- [यूरोपीय आयोग](#) वदियुत संयंत्रों द्वारा वदियुत बेचने के विभिन्न तरीकों पर विचार कर रहा है।
 - वे दीर्घकालिक अनुबंधों का उपयोग करना चाहते हैं जो वदियुत संयंत्रों को उनकी वदियुत के लिये एक निश्चित मूल्य देते हैं।
 - इससे घरों और व्यवसायों के लिये वदियुत की कीमतों को अधिक स्थिर बनाने में मदद मिलेगी।

भारत का नया बाज़ार-आधारित आर्थिक प्रेषण (MBED) मॉडल:

- भारत MBED तंत्र नामक एक नया वदियुत बाज़ार मॉडल विकसित कर रहा है।
 - यह देश की लगभग 1,400 बिलियन यूनिट की वार्षिक वदियुत खपत को प्रेषण के लिये केंद्रीकृत करेगा।
- MBED केंद्र के ['वन नेशन, वन ग्रिड, वन फ्रीक्वेंसी, वन प्राइस'](#) फॉर्मूले के अनुरूप वदियुत बाज़ारों को बढ़ावा देने का एक तरीका है।
 - यह सुनिश्चित करेगा कि पूरे तंत्र की मांग को पूरा करने के लिये देश भर में सबसे सस्ते वदियुत उत्पादन संसाधनों की आपूर्ति की जाए और इसलिये यह वितरण कंपनियों एवं जनरेटर दोनों के लिये फायदेमंद होगा। साथ ही इसके परिणामस्वरूप उपभोक्तकों को बचत भी होगी।
 - यह विकेंद्रीकृत मॉडल स्पष्ट बदलाव को भी चिह्नित करेगा जो [वदियुत अधिनियम, 2003](#) द्वारा समर्थित है।
- वर्तमान में वदियुत ग्रिड को [राज्य लोड डिसपैच सेंटर \(SLDC\)](#) द्वारा प्रबंधित राज्य-वार स्वायत्त नियंत्रण क्षेत्रों में बाँटा गया है जिनका पर्यवेक्षण [क्षेत्रीय लोड डिसपैच सेंटर \(RLDC\)](#) और [नेशनल लोड डिसपैच सेंटर \(NLDC\)](#) द्वारा किया जाता है।
 - MBED मॉडल राज्य के भीतर और एक राज्य से दूसरे राज्य दोनों में वदियुत प्रेषण का एक केंद्रीकृत समय-निर्धारण प्रस्तावित करता है। यह नया मॉडल मौजूदा विकल्पों और डिसिफॉम को सीमित कर देगा तथा [स्टेट लोड डिसपैच सेंटर](#) को वास्तविक समय में बजिली खरीदनी या बेचनी होगी, भले ही यह मांग को संतुलित करने के लिये ही क्यों न हो।
- [GNA \(जनरल नेटवर्क एक्सेस\)](#), जो अधिक खुला और अनुकूलनीय है, को भारत में ऊर्जा ग्रिड के लिये दिशा-निर्देशों के एक नए सेट के रूप में भी विकसित किया जा रहा है।

MBED के केंद्रीकृत मॉडल से जुड़ी चिंताएँ:

- [राज्य की स्वायत्तता पर प्रभाव](#): MBED का राज्यों के वदियुत क्षेत्र के प्रबंधन में सापेक्ष स्वायत्तता पर प्रभाव पड़ेगा, जिसमें उनके स्वयं के उत्पादन केंद्र भी शामिल हैं और यह राज्य के स्वामित्व वाली ज्यादातर [बजिली वितरण कंपनियों \(डिसिफॉम\)](#) को पूरी तरह से केंद्रीकृत तंत्र पर निर्भर कर देगा।
- [उभरते हुए विकेंद्रीकृत बाज़ार के साथ टकराव](#): यह नए बाज़ार के विकास में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न कर सकता है, जैसे कुल ऊर्जा उत्पादन में [नवीकरणीय ऊर्जा](#) का विस्तार और पावर ग्रिड से जुड़ने वाले [इलेक्ट्रिक वाहनों](#) की संख्या में वृद्धि आदि।
 - प्रभावी ग्रिड प्रशासन और संचालन के लिये वास्तव में बाज़ारों और स्वैच्छिक पूलों के व्यापक विकेंद्रीकरण की आवश्यकता है।
- [गरे क्षेत्र](#): कुछ वदियुत संयंत्र, जैसे [मुंबई में ट्रॉम्बे TPS](#) और [NCR क्षेत्र में दादरी TPS](#) को बंद करने के लिये मजबूर किया जाएगा।
 - ये पावर स्टेशन [मुंबई](#) या [दिल्ली](#) जैसे प्रमुख शहरों में सुरक्षा आपूर्ति और ग्रिड फेल होने की स्थिति में संचालन के लिये महत्वपूर्ण हैं।

आगे की राह

- वदियुत भारतीय संविधान की समवर्ती सूची का विषय है, अतः नए मॉडल के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये राज्यों की सफ़ारिशों पर विचार किया जाना चाहिये।
- [सकियोरटी कांस्ट्रेंड इकोनॉमिक डिसिफैच \(SCED\)](#), NLDC द्वारा विकसित एक एल्गोरिथम संभावित समाधान हो सकता है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रव्यापी आधार पर निर्धारित नरिण्यों पर सूचित करने में नियामकों की सहायता करना है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. नमिनलखित कथनों पर विचार कीजिये: (2019)

1. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (PNGRB) भारत सरकार द्वारा स्थापित पहला नियामक निकाय है।

2. PNGRB के कार्यों में से एक गैस के लिये प्रतस्पर्द्धी बाज़ार सुनिश्चित करना है।
3. PNGRB के वदियुत फ़ैसलों के खलिफ अपील अपीलीय न्यायाधकिरण के समकष की जाती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

प्रश्न. नमिनलखिति में से कौन-सा सरकार की एक योजना 'उदय'(UDAY) का उद्देश्य है? (2016)

- (a) ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के कषेत्र में स्टार्टअप उदयमयिों को तकनीकी और वत्तीय सहायता प्रदान करना।
- (b) वर्ष 2018 तक देश के हर घर में वदियुत पहुँचाना।
- (c) कोयला आधारति वदियुत संयंत्रों को समय के साथ प्राकृतिकि गैस, परमाणु, सौर, पवन और ज्वारीय वदियुत संयंत्रों से बदलना।
- (d) वदियुत वतिरण कंपनयिों के बदलाव और पुनरुदधार के लिये वत्ति प्रदान करना।

उत्तर: (d)

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Referenece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/current-affairs-news-analysis-editorials/news-analysis/30-01-2023/print>